पंचदश

बिहार विधान-सभा

चतुर्दश सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-3

बुधवार, तिथि 11 आषाढ़ 1936 (श0) / 02 जुलाई, 2014 (ई0)

प्रश्नों की कुल संख्या 03

(1) पथ निर्माण विभाग	..	..	01
(2) जल संसाधन विभाग	..	..	01
(3) ग्रामीण विकास विभाग	..	..	01
		कुल योग ..	03

कार्य पूरा करना

3. श्री मंजीत कुमार सिंह—क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि एस0एच0 78 बिहटा–सरमेरा पथ 94.2 कि0मी0 के निर्माण हेतु 391 करोड़ की परियोजना को बी0एस0आर0डी0सी0 ने हैदराबाद की निर्माण कम्पनी रैमकी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अप्रैल, 2010 में करार किया था, मई, 2013 में उसका निर्माण कार्य पूरा हो जाना था जो अबतक पूर्ण नहीं किया जा सका है ;

(2) क्या यह बात सही है कि एस0एच0 90 महम्मदपुर–राजापट्टी–मशरक–खैरा–छपरा रोड का निर्माण एशियन डवलपमेंट बैंक की ऋण राशि से हो रहा है, का 64.71 कि0मी0 सड़क के निर्माण का जिम्मा हैदराबाद की निर्माण कम्पनी सदभाव इंजीनियरिंग को था एवं 201 करोड़ की इस परियोजना का कार्य आरंभ अक्टूबर, 2011 में तथा अप्रैल, 2013 तक कार्य समाप्त किया जाना था परन्तु अबतक पूर्ण नहीं हो सका है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक कार्य पूर्ण कराने का विचार रखती है ?

लंबित योजनाओं को पूरा करना

4. श्री नितिन नवीन—क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग में 4300 सौ करोड़ की योजनायें लंबित हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि बाढ़ नियंत्रण की दस योजनाओं को स्वीकृति हेतु गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग वर्ष 2012–13 में भेजा गया, जिसकी आजतक स्वीकृति नहीं प्राप्त हुई है ;

(3) क्या यह बात सही है कि बाढ़ नियंत्रण की 331 योजनाओं में से 312 पर वर्ष 2013–14 में कार्य किये गये हैं, इनमें आजतक 152 योजनाओं का कार्यारम्भ भी नहीं किया गया है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त लंबित योजनाओं को कबतक पूरा करने का विचार रखती है और नहीं, तो क्यों ?

दोषी पर कार्रवाई

5. श्री अब्दुलबारी सिद्दिकी—दिनांक 28 मई, 2014 को स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार–पत्र "दैनिक जागरण" में प्रकाशित शीर्षक 72.5 लाख जॉब कार्ड रद्द को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि मनरेगा योजना में पारदर्शिता बनाये रखने के लिये सरकार ने दिनांक 27 मई, 2014 को 72.5 लाख जॉब कार्ड को रद्द कर दिया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त जॉब काडों में वैसे जॉब कार्ड भी शामिल हैं जो सरकारी कर्मियों तथा एक ही व्यक्ति के नाम पर कई कार्ड निर्गत किये गये हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो 72.5 लाख में सरकारी कर्मियों के नाम पर कितना कार्ड तथा एक ही व्यक्ति के नाम पर बनाये गये कई–कई कार्ड के हिसाब से कुल कितना जॉब कार्ड निर्गत है और उन 72.5 लाख फर्जी जॉब कार्ड के विरुद्ध कुल कितनी राशि का भुगतान हुआ है तथा इसके लिये दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार कौन–सी कार्रवाई करने का विचार रखती है ?

पटना :
दिनांक 2 जुलाई, 2014 (ई0)।

हरे राम मुखिया,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान–सभा।

बि0स0मु0 (एल0ए0), 36–डी0टी0पी0–450